अत्यंत महत्वपूर्ण
विधानसभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419 औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली 110092

फा.सं0 सी.आई / डी.सी.आई. / क्यू.सी. / 2019 / 474 - 77 दिनांक : 22/8/19.

सेवा में,

उपसचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

विषयः दिल्ली विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 17 दिनांक 22.08.2019 को सदन की बैठक हेतु।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्वत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

यह सूचना सक्ष्म पदाधिकारी की स्वीकृति से जारी है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

विनोद कुमार
(विनोद कुमार)
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

प्रतिलिपि :

1. सचिव , माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय , दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित ।
3. सचिव, माननननीय रोजगार मंत्री, ए –विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

विनोद कुमार
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

विभाग का नाम :– कार्यालय आयुक्त उद्योग
विभाग का पता:–कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली–110092

तारांकित प्रश्न संख्या – 17
दिनांक : 22.08.2019
प्रश्नकर्ता:– श्री पवन कुमार शर्मा

सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या भारत सरकार की "स्टार्ट–अप इंडिया योजना" को दिल्ली में लागू किया गया है ;	"स्टार्ट–अप इंडिया योजना" की तर्ज पर दिल्ली में यह पॉलिसी लागू करने की स्वीकृति अभी नहीं हुई है।
ख	यदि हां, तो मार्च 2019 के बाद से इस योजना के लाभार्थियों की क्या संख्या है ;	उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं होता।
ग	इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिये क्या मानदंड हैं ; और	
घ	क्या इस योजना में दलित वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लिये कोई विशेष प्रावधान है ?	

अरविन्द राणा

(अरविंद राणा)
उपायुक्त उद्योग

उपायुक्त उद्योग (प्र.शा.)

Material for Supplementary Vidhan Sabha starred Question No-17, due for reply on 22.08.2019

The Start-up India is a Programme initiative by the Government of India to generate employment opportunity . On this pattern, a draft Start-up policy has been framed for Delhi, which is yet to be approved by Competent authority.

The Chief Secretary has nominated the Industries Department as Nodal Department for Start-up Projects and Pr. Secretary-cum-Commissioner (Industries) as Nodal Officer.

The Industries Department, GNCTD has formulated the draft Start-up policy for Delhi and is in the process of setting up of an Innovation/Incubation Centre in Delhi.

The key sectors/areas where Delhi Government is focusing for developing world class innovation/incubation centre are:- (i) Renewable Energy & Environment Protection, (ii) Artificial Intelligence, (iii) Cyber Security & Technical Innovation, (iv) Automation, (v) Education, (vi) Urban Infrastructure Planning & Development, (vii) Big Data, (viii) Solid- Waste Management, (ix) Control of Ambient Air Pollution, (x) Robotics.

The name of the centre will be:- DELHI INNOVATION CENTRE

Delhi Emporium Building, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi, having total 7,476 sq. ft carpet areas (I, II & IIIrd Floor-2, 492 Sq. ft area at each floor) has been identified for setting up of Delhi Innovation Centre and the file on this matter is under submission to the higher authorities.

Delhi Incubation Centre shall have the state of the art facilities like Conference halls, Meeting rooms, Video Conferencing facilities, High Speed internet, Wi-fi connectivity, Co-working space, Mentor access and other common business services.

Initially GNCTD will support financially in setting up of the incubation centre completely and it will be run by an agency/company headed by CEO, who will be appointed by the Advisory Committee.

The main objective of the Delhi Startup policy will be to facilitate and nurture the growth of at least 5000 new startups in Delhi in next five years. Establishing minimum 2,50,000 sq. ft area for incubation centers and additionally, support 2,50,000 sq. ft of existing incubator infrastructure during the policy term. Facilitating set up of Tinkering Labs in every Secondary and Higher-secondary school by 2025. Setting up of 05

fabrication labs in Delhi by 2023 & establishing 100 Entrepreneurship Development Cells in National Capital Territory by 2023.

After consultation with various Stakeholder Departments of GNCTD, proposal is being submitted for approval of the Cabinet.